हिन्दू 15-03-23

राष्ट्रीय

- राज्यपाल के खिलाफ तेलंगाना की अपील पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
  SC ने मंगलवार को तेलंगाना सरकार और तमिलसाई साउंडराजन के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों को पारित करने से इनकार करके "संवैधानिक गतिरोध पैदा करना" था।
  राज्य ने अदालत से "यह घोषित करने का आग्रह किया कि गवर्नर द्वारा बिलों की स्वीकृति के संबंध में निष्क्रियता, चूक और संवैधानिक जनादेश का पालन करना अवैध है।"
- महाराष्ट्र विवादित सीमावर्ती गांवों में प्रमुख स्वास्थ्य योजना का विस्तार करता है। महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के नियंत्रण वाले 854 जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) शुरू करने का निर्णय लिया। ये गांव कर्नाटक के बीदर, बेलाघवी कारवार और कलबुर्गी जिलों के अंतर्गत आते हैं।
  1966 से महाराष्ट्र ने सीमावर्ती क्षेत्रों के कई हिस्सों पर अधिकार का दावा किया है जो कर्नाटक के नियंत्रण में है, यह विवाद अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में झुका हुआ है।
  पिछले साल नवंबर में तनाव बढ़ गया था क्योंकि दोनों पक्षों ने दावा किया था कि बाद में वहां के इलाकों में तनाव बढ़ गया था। बाद में जब सीएम गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो पारा पिघल गया।
  सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड से और पैसे मांगने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कंपनी से लगभग 676 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग को लेकर केंद्र की उपचारात्मक याचिका को खारिज कर दिया।
  कोर्ट ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है और जो समझौता किया जाना था वह 1989 में किया जाना चाहिए था, जब पीड़ितों को यूसीसी भुगतान के बारे में समझौता चल रहा था।
  भोपाल गैस त्रासदी 02-03-1984 को हुई थी, जिसमें एमआईसी (मिथल आइसो सायनेट) के रिसाव से पांच हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी। एमआईसी का सामना करने वाले कई अन्य लोगों के बच्चे में जन्म दोष थे।
  SC ने हालांकि बताया कि पीड़ितों को भुगतान के संबंध में "घोर लापरवाही" हुई थी।
- सरकार का कहना है कि ओबीसी पैनल के पास जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं हैं

न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग, 2017 में गठित किया गया था → इसे जो कार्य दिया गया था, वह ओबीसी के तहत 3000 जाति समूहों को उप-वर्गीकृत करना था।

लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि कौन से जाति समूहों को आरक्षण के लाभों तक सबसे अधिक पहुंच प्राप्त थी, जो कम विशेषाधिकार प्राप्त जाति समूहों को भीड़ से बाहर कर रहे थे।

इस बारे में सवाल पूछा गया था कि क्या यह समूह सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 12011) पर विचार कर रहा है। इसका जवाब देते हुए सामाजिक न्याय मंत्री ए.

नरगस्वामी ने कहा कि पैनल ने इस संबंध में केंद्र से SECC, 2011 के डेटा का अनुरोध नहीं किया था।

एसईसीसी का जाति डेटा सार्वजनिक डोमेन में नहीं है।

- ⇨ जनजातीय मामलों पर हाउस पैनल जनसंख्या डेटा के बिना पीएम-पीवीटीजी परिव्यय के बारे में आशंकित है।

  बजट 2023 में, एफएम ने विकास मिशन के लिए 'पीएम-पीवीटीजी प्रधान मंत्री - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)' के लिए 15,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की थी। हाउस बैंड ने चिंता जताई है कि इतनी बड़ी राशि बिना पीवीटीजी के उचित डेटा के आवंटित की गई है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने PVTGs पैनल पर डेटा नहीं बताया है

  - पीवीटीजी डेटा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जल्द से जल्द तैयार किया जाना चाहिए।
  - इसने चिंता जताई कि 2022-23 में सरकार आवंटित 252 करोड़ में से केवल 6.48 करोड़ ही खर्च कर पाई

- ⇨ भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की अनुमति दी है भारतीय रुपये में भुगतान निपटाने के लिए 18 देशों के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता (एसवीआरएएस) खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार। मंगलवार को राज्यसभा में बताया। बैंकों से - बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी गुयाना, इज़राइल, केन्या, मलेशिया, मॉरीशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, द सेशेल्स सिंगापुर, सोइलंका, तंजानिया, युगांडा और यूके को आरबीआई के साथ व्यापार करने के लिए सुरा खोलने की अनुमति दी गई है रुपये में खाड़ी। रुपये में व्यापार से भारत को अपना निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी।
- ⇨ यू.एस. राजदूत नामित एरिक ग्रेसेटी पुष्टि से पहले बाधा का पता लगाने के करीब हैं, वर्तमान में कोई भी अमेरिकी राजदूत भारत के अमेरिका में नहीं है। राजदूत दो साल से भारत के अमेरिकी दूतावास में है। अमेरिका एरिक ग्रेसेटी को प्रोसेस कर रहा है ताकि जी-20 के लिए जो बाइडेन की भारत यात्रा से पहले वह भारत में हों
- ⇨ 18 अफगान विदेश मंत्रालय के पाठ्यक्रम, आईआईएम कोझीकडे में शामिल हुए।

  ITEC (भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग) पर लघु अवधि के ऑनलाइन पाठ्यक्रम अफगानिस्तान में आयोजित किए गए। थाईलैंड, मालदीव के छात्र वर्चुअली जुड़े।
- ⇨ आपदा राहत के लिए भारत का पहला उत्तरदाता जनरल: चौहान कहते हैं।
- ⇨ कैबिनेट सचिव गर्मियों में बैठक बुलाते हैं।
- ⇨ लेखक पेरुमल मारगन शुद्ध अंतरराष्ट्रीय विशेषता से रोमांचित हैं

बुकर चिता -

ACHIEVERS IAS ACADEMY

PYRE - तमिल उपन्यास "पुकुझी" का अंग्रेजी अनुवाद
लिखते हैं → पेरुमल मुरुगन

- 1993 से सीवर की सफाई के दौरान 1035 लोगों की मौत : केंद्र
- सुरेखा वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला हैं। पूरा नाम सुरेखा यादव
- एक अन्य अमेरिकी नौसेना जहाज मरम्मत के लिए एलएंडटी शिप यार्ड में आता है।
- राहुल के भाषण पर विवाद संसद को बाधित करता है। राहुल के लंदन वाले बयान पर बीजेपी ने मांगी माफी
- बीजेपी का कहना है कि राहुल की सदन में उपस्थिति "औसत से कम" है।
- कांग्रेस ने धनखड़ बैठक में विदेश में की गई मोदी की टिप्पणी का हवाला दिया।
- अडानी विवाद को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ अभियान तेज किया

<u>दुनिया</u>

- ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी वाइन्डर AUKUS को खरीदेगा।
  ऑस्ट्रेलिया ने पांच परमाणु संचालित पनडुब्बी खरीदने की योजना को परिवर्तित किया है, फिर एक महत्वाकांक्षी योजना में यू.एस. और ब्रिटिश प्रौद्योगिकी के साथ एक नया मॉडल तैयार किया है। योजना एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते चीन को विफल करने की है।
  घोषणा सैन-डिएगो (यूएसए) से हुई, जहां जो बिडेन, ऋषि सनक और एंथोनी अल्बनीस AUKUS के तहत मिले। यह सौदा ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमता में सबसे बड़ा एकल निवेश है, जिसे ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनेस ने बताया। इसकी लागत 10 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया और 40 बिलियन डॉलर होगी।
  IAEA (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी) ने कहा है कि इस सौदे को "कोई प्रसार जोखिम नहीं" सुनिश्चित करना है A/c IAEA दिशानिर्देश "परमाणु राज्य गैर-परमाणु राज्यों को परमाणु सामग्री स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह गैर-परमाणु राज्यों के रूप में बनाने के जोखिम को बढ़ा देगा। पनडुब्बी परमाणु बम। चूंकि पनडुब्बियां परमाणु संचालित में स्थानांतरित हो जाती हैं, इसलिए यह चिंता पैदा होती है।
  इस डील को करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को IAEA की सुरक्षा से गुजरना होगा।
  AUKUS - ऑस्ट्रेलिया + यूके + यूएसए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता (18 महीने पुराना)
  IAEA - अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी HC - विकना
  प्रमुख – राफेल ग्रॉसी
- चीन का कहना है कि AUKUS सौदा "गलत और खतरनाक रास्ते" पर जा रहा है। 'चीन ने परमाणु संचालित सबमिशन ऑस्ट्रेलिया को हस्तांतरित करने के लिए AURUS सौदे का कड़ा विरोध व्यक्त किया है। हमें बार-बार कहा जाता है कि तथाकथित AUKUs सुरक्षा साझेदारी की स्थापना के बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि परमाणु पनडुब्बियों और अन्य अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यू.एस. यूके और ऑस्ट्रेलिया एक सामान्य ठंडी मानसिकता है। बीजिंग में।
- चीन ने महामारी के कारण लगे 3 साल के प्रतिबंधों के बाद पर्यटकों के लिए सीमाएं खोलीं।

ACHIEVERS IAS ACADEMY

COVID के कारण चीन में सबसे सख्त यात्रा प्रतिबंधों में से एक है। अंतिम। पिछले साल इसने कुछ छात्रों और अन्य पेशेवरों को चीन में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। चीन ने दिसंबर 2012 में अपनी शून्य-कोविड नीति को समाप्त कर दिया। इसने 3 जनवरी को परिवार के पुनर्मिलन के लिए अपनी सीमाओं को खोल दिया। अब इसने किसी भी प्रतिबंध को हटा दिया है। सभी चीनी दूतावास। दुनिया भर में वीजा कैसे जारी कर सकते हैं

- अर्मेनियाई प्रधान मंत्री ने रूस द्वारा सुरक्षा गठबंधन की आलोचना की। अर्मेनियाई प्रधान मंत्री निकोल पशिनयान ने मंगलवार को मास्को-प्रभुत्व वाले सुरक्षा गठबंधन (सीएसटीओ) पर अज़रबैजान से खतरे के सामने अपने देश को ठंड में छोड़ने का आरोप लगाया।
  सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ)। यह आर्मेनिया, बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान से आने वाला एक सैन्य एलियाना है।
  रूस अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया का साथ नहीं दे पाया है। यूक्रेन के साथ रूस की भागीदारी एक मुख्य कारण है। और रूस एक तेल समृद्ध देश अजरबैजान के खिलाफ नहीं जाना चाहता।
- आर्मेनिया - अज़रबैजान संघर्ष - नागोर्नो-काराबाख एक अजरबैजान का क्षेत्र है जिसमें अर्मेनियाई लोगों का प्रभुत्व है। यहां के अर्मेनियाई लोग नागोर्नो काराबाख का अर्मेनिया में विलय करना चाहते हैं आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख आंदोलन का समर्थन करता है।
  अज़ेसबैज़म = तुर्की द्वारा समर्थित
  आर्मेनिया = रूस द्वारा समर्थित।
  2022 में भारत ने अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लांचर की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की थी।
- पुतिन ने कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम विस्फोट राज्य स्तर पर किए गए थे 'उन्होंने इस विचार को एक स्वायत्तता से खारिज कर दिया
  इसके लिए यूक्रेन समर्थक समूह जिम्मेदार था।
  नॉर्ड स्ट्रीम - स्ट्रीम - यूरोप को रूसी गैस आपूर्ति पाइपलाइन जिसमें विस्फोट हो गया था, वर्ष सितंबर खो गया
- सऊदी अरब ने बोइंग से 12 जेटलाइनर तक का ऑर्डर दिया।
- चीन के साथ तनाव बढ़ने पर ताइवान ने पोस्टेबल अटैक ड्रोन का खुलासा किया।
- स्वीडिश पीएम का मानना है कि फिनलैंड की नाटो प्रविष्टि की पुष्टि पहले की जाएगी। नाटो के लिए स्वीडन की बोली अभी भी तुर्की के विरोध का सामना कर रही है।
- इमरान की गिरफ्तारी आसन्न: विरोध शुरू
  इमरान खान ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में अपने समर्थकों से वास्तविक आजादी के लिए 'बाहर आने' और मर जाने पर भी संघर्ष जारी रखने को कहा।
  भगवान ने एक को सब कुछ दिया है और मैं आपके लिए यह लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं जीवन भर यह लड़ाई लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा, अगर मुझे कुछ हो जाता है और मुझे जेल भेज दिया जाता है या मुझे मार दिया जाता है, तो आपको यह साबित करना होगा कि आप इमरान खान के बिना संघर्ष करेंगे और चोरों की गुलामी स्वीकार करेंगे और एक व्यक्ति जो देश के लिए निर्णय ले रहा है”
  इस संदेश के जारी होते ही इस्लामाबाद पेशावर, कराची कुएला फैसलाबाद आदि कई शहरों में विरोध शुरू हो गया।

ACHIEVERS IAS ACADEMY

इससे पहले कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ मोनवारंट जारी किया था, ताकि लाहौर में उनके घर को उनके समर्थकों ने घेर लिया हो। पुलिस भीड़ को तितर-बितर करते हुए धीरे-धीरे वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है।

- रूसी लड़ाकू ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया: अमेरिका एक रूसी लड़ाकू विमान ने मंगलवार को काला सागर के ऊपर अमेरिकी निगरानी ड्रोन के प्रोपेलर पर हमला किया, जिससे अमेरिकी बलों को अज्ञात रूसी एसयू-27 ड्रोन को मार गिराया, जबकि हालत परीक्षण ने अंतरराष्ट्रीय जल में अमेरिका के एमक्यू-9 ड्रोन को मार गिराया। . व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की

संपादकीय-1

जड़ता, हस्तक्षेप

सामाजिक मुद्दों पर विधायिका की निष्क्रियता न्यायिक हस्तक्षेप को वैध करेगी

- संपादकीय किस बारे में है?

संपादकीय "समान-लिंग मुद्दे" के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पांच न्यायाधीशों की उच्च पीठ में स्थानांतरित कर दिया है। केंद्र का रुख समलैंगिक विवाह के खिलाफ है। संपादकीय ने इस संबंध में सरकार की भारी आलोचना की है।

- समलैंगिक विवाह के बारे में हाल ही में क्या विकास हुआ है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए समान-सेक्स जोड़े द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देना समानता के अधिकार के खिलाफ है। यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सरकार से राय मांगी थी।

सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने के पक्ष में नहीं है। गाउट द्वारा समलिंगी विवाह के विरुद्ध दिए गए कुछ कारण

- विवाह एक पवित्र संस्था है जिसमें एक पुरुष एक महिला है
- समलैंगिक विवाह धार्मिक लोकाचार और सांस्कृतिक मानदंडों के खिलाफ है।
- व्यक्तिगत कानून समलैंगिक विवाह आदि की अनुमति नहीं देते हैं।

एक सरकार ने दृढ़ता से कहा है कि विवाह के बारे में कोई भी कानून विधायिका से आना चाहिए न कि न्यायपालिका से।

- अलग-अलग कानून क्या हैं, और समान लिंग वाले जोड़े के बारे में पहले के एससी निर्णय क्या हैं?

इससे पहले 2018 में, SC ने समलैंगिक जोड़े के बीच संभोग को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ज्ञात मामला नांत - जौहर केस।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 उन वर्गों को अनुमति देता है जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं हैं। विवाह के रूप में माना जाएगा। SC समलैंगिक विवाह को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत ला सकता है

- आगे का रास्ता।

समान लिंग विवाह को कानूनी स्थिति दी जानी चाहिए। यह समाज को और अधिक समान बनाएगा। संपत्ति विवाद, बच्चों को गोद लेने आदि के बारे में सरकार की चिंता बहुत दयनीय मुद्दे हैं।

ACHIEVERS IAS ACADEMY

सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार का भी कोई महत्व नहीं है। सरकार को इसे काफी पहले वैध कर देना चाहिए था।
संपादकीय देखता है कि समलैंगिक विवाह के अधिकारों को जल्द से जल्द कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए।

<u>संपादकीय-2</u>

स्पिन मुसीबत

ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने आईसीसी ट्रॉफी पर एक और निशाना साधा है।

- ⇨ संपादकीय किस बारे में है?
  संपादकीय में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराने की बात कही गई है। भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए भी क्वालीफाई किया। संपादकीय में उम्मीद की जा रही है कि जून में डब्ल्यूटीसी जीतकर भारत 2013 से आईसीसी चैंपियन ड्राफ्ट को खत्म कर देगा।
- ⇨ WTC क्या है? और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के परिणाम के बारे में।
  WITC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हर 2 साल में खेली जाती है, यह 7 जून से लंदन के ओवल में खेली जाएगी।
  अंतिम WTC 2021 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। भारत वहां हार गया था।
  भारत ने डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
  फाइनल 7 जून से लंदन में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होगा।
  हाल ही में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में, पहले 3 टेस्ट में स्पिनरों के हावी होने के साथ मैच कम स्कोर वाले थे।
- ⇨ WTC फाइनल के लिए भारत की तैयारी के बारे में। इंग्लैंड की पटरियां गति के अनुकूल होंगी। बुमराह, शमी, सिराज और उमेश वहां अगुआई करेंगे। भारत स्पिनर के तौर पर रवींद्र जुडेजा और आर. अश्विन में से किसी एक को चुन सकता है। भारत की बल्लेबाजी का मूल रोहित, पुजारा, कोहली ने इस टूर्नामेंट में रन बटोरे, यह शुभ संकेत टेस्ट क्रिकेट में अपनी फॉर्म से जुड़ रहे शुभमन गिल भारत के लिए शुभ संकेत

ACHIEVERS IAS ACADEMY